

नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से किया इनकार, आखिर क्यों?

विशेषज्ञों की मानें तो, या तो वे एनडीए में अपनी अर्थॉरिटी साबित कर रहे हैं या फिर कोई और बड़ा खेल करना चाहते हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 नवम्बर। बिहार विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत मिलने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और इस दौरान इस्तीफ़ा देने से इनकार करके बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी। इस कदम ने उनके अगले क्रदमों को लेकर अटकलों को और बढ़ा दिया है और इससे नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के अंदर नई दरारें उजागर हो गई हैं।
एनडीए की भारी जीत के बावजूद, नीतीश की चुप्पी और उनकी रणनीतिक मुद्रा ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे किसी प्लान बो की संभावना तलाश रहे हैं, जिसमें भाजपा शामिल न हो। शनिवार को भाजपा नेताओं ने दावा

- एनडीए की इकतरफा जीत के बाद भी नीतीश चुप हैं और उनकी चुप्पी से राजनैतिक हलकों में खलबली मच गई है, खासकर एनडीए में।
- नीतीश ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। मौन और इनकार से नीतीश ने भाजपा से सौदेबाजी करने की ताकत बढ़ा ली है और जिस प्रकार भाजपा ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया है, उससे जाहिर है कि नीतीश अपनी नीति में सफल हो रहे हैं।
- लेकिन, नीतीश इतने से ही संतुष्ट नहीं होंगे, इस बार वे अपनी शर्तों पर सरकार बनाएंगे। समझा जाता है कि नीतीश ने स्पीकर और उपमुख्यमंत्री के पद पर दावा तो किया ही है, साथ ही बिहार के लिए विशेष पैकेज भी मांगा है।
- इसी बीच यह भी चर्चा है कि महागठबंधन ने नीतीश को समर्थन देने की पेशकश की है। नीतीश के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पाला बदलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

किया कि पार्टी हाईकमान को नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने पर “कोई आपत्ति नहीं” है, लेकिन जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर की गतिविधियां बताती हैं कि अंदर ही अंदर कोई जटिल सौदेबाजी चल रही है।

जेडीयू नेतृत्व से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने भाजपा को साफ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश की निर्वासित प्र.मंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड

बांग्लादेश सरकार द्वारा गठित इंटरनैशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधी करार देकर मौत की सजा सुनाई

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 नवम्बर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक ट्रिब्यूनल ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के दौरान अपराध करने और पुलिस को घातक कार्रवाई के आदेश देने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाए जाने के साथ ही, उनकी देश वापसी की मांग तेज हो गई है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने भारत से मांग की है कि वह शेख हसीना को वापस भेजे, जो आंदोलन के बाद भारत आ गई थी। मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पहले ही हसीना को उनके अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए वापस भेजने की मांग कर चुकी है। लेकिन भारत ने अब

- शेख हसीना ने फैसले को एकतरफा और पक्षपातपूर्ण करार दिया और कहा कि कथित इंटरनैशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल में किसी भी अन्य देश का कोई भी कानूनी विशेषज्ञ नहीं था।
- बांग्लादेश की तरफ से भारत सरकार से लिखित में मांग की गई है कि शेख हसीना फरार अपराधी हैं, उन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, ऐसा नहीं करना गैर मित्रतापूर्ण कृत्य माना जाएगा।
- शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भी चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह वही पार्टी है, जिसने पाकिस्तान के अत्याचारों से बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी।

तक इस मांग को न तो माना है और न ही अंतरिम सरकार के दावे को मान्यता दी है। शेख हसीना ने अपनी तरफ से

कहा है कि अंतरिम सरकार ने इन्टरनैशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘स्पीकर तय करें, न्यू ईयर कहां मनाना चाहते हैं’

नई दिल्ली, 17 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने

- सीजेआई ने तेलंगाना स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के दस विधायकों की अयोग्यता पर जल्दी फैसला करें अन्यथा इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष ने बीआरएस के 10 विधायकों जो कांग्रेस में शामिल हो गए, के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अदालत द्वारा तय समयसीमा में निर्णय नहीं लिया। चीफ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य सरकार ने एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ अपील की

जयपुर, 17 नवंबर। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ करीब ढाई माह बाद अब राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। परीक्षा केन्द्र से जो पेपर लीक हुआ था, वह कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंचा था। इसके अलावा आरपीएससी के सदस्यों के जरिए लीक होने वाला पेपर भी उनके बच्चों और दलालों तक ही पहुंच पाया था। यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही

- हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पेपर लीक के कारण एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को 28 अगस्त को रद्द किया था।

और गलत की छंटनी कर सकती हैं तो कानून पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द करने के संबंध में राज्य सरकार और आरपीएससी को निर्देश दिए थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 8 सितम्बर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनावी हार के लिए बलि का बकरा ढूंढ रही है कांग्रेस

न कोई जिम्मेदारी, न जवाबदेही, फिर सफलता कैसे मिलेगी

- कांग्रेस ने बिहार में हार को अस्वीकार कर दिया है और “वोट चोरी” को ही हार का कारण बताया जा रहा है।
- वहीं पंजाब में जीत का दावा कर रही कांग्रेस उपचुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाई तो पीसीसी अध्यक्ष राजा वडिंग से इस्तीफा लेने की तैयारी की जा रही है, जबकि पंजाब में भूपेश बघेल बतौर प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल के कहे अनुसार काम कर रहे थे।
- मंगलवार को राहुल गांधी ने उन 12 राज्यों के पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं की बैठक बुलाई है, जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि यह सब बिहार की हार से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी पार्टी की दुर्दशा का एक बड़ा कारण राहुल के प्रतिनिधि के तौर पर पार्टी चला रहे के.सी. वेणुगोपाल की मनमानी को माना जा रहा है।

चोरी” की बातों पर ही ध्यान दे रहे हैं, और वे यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि बिहार में उन्हें करारी हार मिली है। उच्च स्तर के सूत्रों के अनुसार, नाराज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि पार्टी हर जगह क्यों हार रही है, फैसले कौन ले रहा है और किसी पर भी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही। स्पष्ट है कि खडगे का निशाना वेणुगोपाल, और पार्टी को राहुल के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप का दबाव काम आया, भारत अमेरिका से एलपीजी खरीदेगा

भारत ने अमेरिका से एक साल की डील की है, जिसमें 22 लाख टन एलपीजी खरीदी जाएगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 नवंबर। मोदी सरकार का अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का पहला ठोस सबूत सामने आया है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) आयात के लिए एक साल का समझौता किया है। यह भारतीय बाज़ार के लिए अमेरिकी एल.पी.जी. का पहला व्यवस्थित अनुबंध है।

हालाँकि इस कदम को देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और व्यापार समझौते की बातचीत के बीच अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, लेकिन साफ़ दिखता है कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की धमकाने वाली दबाव नीति के आगे

- सरकार द्वारा इसे देश के ऊर्जा स्रोतों को विविधता देने का प्रयास बताया जा रहा है, पर आलोचक इसे ट्रंप की धमकी के आगे घुटने टेकना बता रहे हैं।

- जानकारी सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख तेल कंपनियाँ अमेरिका से एलपीजी खरीदेंगी।
- भारत की एलपीजी की आवश्यकता अधिकांशतः सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और कुवैत से पूरी होती है। इस डील से इन देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी।

झुक गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनका नाम, कुख्यात एस्पटीन फाइलों में आने के कारण सवालों के घेरे में है, ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस सौदे को “ऐतिहासिक पहल” बताया। उन्होंने कहा, “दुनिया के सबसे

बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ रहे एल.पी.जी. बाजारों में से एक, अब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खुल गया है। भारत के लोगों को सुरक्षित और सस्ती एल.पी.जी. उपलब्ध कराने का प्रयास में हम लगातार अपने स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारतीय पी.एस.यू.

तेल कंपनियों ने 2026 के लिए लगभग 2.2 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) एल.पी.जी., जो हमारे सालाना आयात का लगभग 10 प्रतिशत है, यह समझौता वर्ष 2026 के लिए अमेरिका के खाड़ी तट से आयात करने के लिए है। यह भारतीय बाज़ार के लिए अमेरिकी एल.पी.जी. का पहला औपचारिक अनुबंध है। जानकारी सूत्रों के अनुसार, तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियाँ- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बी.पी.सी.एल.) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एच.पी.सी.एल.) ने अगले साल के लिए अमेरिकी एल.पी.जी. आयात का संयुक्त टेंडर शेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जी टेंडिंग को दिया है। सौदे का व्यावसायिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

भारत में एल.पी.जी. का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना पकाने के ईंधन के रूप में होता है और इसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत जैसे देशों से आयात होता है। एक अधिकारी ने इस परिवर्तन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वी. श्रीनिवास ने मुख्य सचिव का पद संभाला

जयपुर, 17 नवंबर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास ने सोमवार को राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने उन्हें औपचारिक रूप से चार्ज सौंपा। चार्ज लेने से पहले दोनों अफसरों ने सचिवालय भवन के प्रवेश द्वार स्थित गणेश मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की। चार्ज संभालने के बाद श्रीनिवास ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि सुधांशु पंत को सचिवालय में आईएएस एसोसिएशन की ओर से विदाई दी गई। पंत अब दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में विशेष अधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

वापस आना था। इन 54 में से चार लोग एक कार से मक्का से मदीना जा रहे थे और चार अन्य लोग मक्का में ही रुक गए थे। बाकी लोग हादसे का शिकार हुई बस में सफर कर रहे थे। हादसे के समय बस में 46 लोग सवार थे। हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि हमें जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक 45 लोग मारे गए हैं और ये लोग 23 नवंबर को हैदराबाद लौटने वाले थे। एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन ने भी बताया कि हमें जो शुरुआती रिपोर्ट मिल रही है, उसके तहत हादसे में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हम पीडित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद

से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से हादसे में मारे गए लोगों के शवों को वापस भारत लाने में मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब हादसे पर दुख जताया। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुए हादसे से बेहद दुखी हूँ। पीडित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दाह का महावाणिज्य दूतावास हरसंभव मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारे अधिकारी भी सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों के संपर्क में हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन स्थलों के लिए वीआर शो की रूपरेखा तैयार करने के दिये निर्देश

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के दिए निर्देश

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सोमवार को प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मिण रियाड़ की उपस्थिति में शासन सचिवालय में पर्यटन विभाग एवं कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यो एवं योजनाओं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन और कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यो एवं योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए साथ ही समय बढ़ता से लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए।

दिया कुमारी ने महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सिक्रिट, शेखावाटी हवेलियों, ट्राईबल सिक्रिट, जवाहर कला केंद्र, शिल्पग्राम जैसे विकास कार्यो पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक में पर्यटन विभाग के मार्केटिंग शाखा द्वारा एआर/वीआर शो की रूपरेखा के संबंध में चर्चा की।



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ की उपस्थिति में शासन सचिवालय में बैठक ली।

उन्होंने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए एआर/वीआर शो की रूपरेखा तैयार करने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने उक्त समीक्षा बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा झुन्झुनू में बनवाये जाने वाले वार म्युजियम की चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री को ट्यूर्यूरिज्म ऐप हेतु जानकारी दी गई कि इस हेतु बोली की तैयारी

प्रक्रियाधीन है। दिया कुमारी को पर्यटन विभाग की विकास शाखा/टीआरसी जयपुर की ओर से जेडीए को जयपुर में कॉन्स्टर्ट पर्यटन के विकास हेतु पूर्व में आरक्षित भूमि को आवंटित करने का अनुरोध करने की जानकारी दी गई। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि होटल के लिए जेसीटीएसएल द्वारा की जा रही

कार्यवाही से अवगत कराया गया। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर वाल्ड सिटी वर्क तकनीकी बोलियों अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार ए एण्ड एम द्वारा अलबर्ट हाल वर्क हेतु प्राप्त ई-निविदाएँ समीक्षा प्रक्रिया में है। आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले आमेर मास्टरप्लान पर भी चर्चा की गई।

अनिल मलिक ने चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर का किया निरीक्षण

जयपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अनिल मलिक ने जयपुर के रामनगरिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र, जयपुरिया अस्पताल में परिसर में स्थित वन स्टॉप सेंटर और मानसरोवर में बाल अधिकारिता विभाग के तहत संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण किया। मलिक ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत : डॉ. किरोड़ी लाल

जयपुर। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। वे मौसम बारिश, अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की समीक्षा के बाद सरकार ने 43 लाख 39 हजार किसानों को 2,600 करोड़ रुपये के कृषि आदान-अनुदान वितरण का निर्णय लिया है।

आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि वर्ष 2025 में हुई बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रदेश के 30 जिलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराब हुई है, जबकि 11 जिलों में फसल नुकसान 33 प्रतिशत से कम आंका गया है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार 24 जिलों के 14,687 गांवों के कुल 43 लाख 39 हजार किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ नियमों के तहत राहत राशि वितरित की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि असामान्य बारिश के कारण प्रदेश में सार्वजनिक परिसंपत्तियों को भी गंभीर क्षित पहुंची है। इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार ने 50,3०8 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है, जिन पर 1,012

- सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया**
- बारिश और आपदाओं के कारण हुई 112 जनहानि में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई**

करोड़ 61 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है। इनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत के 14,212 कार्यों पर 293 करोड़ 13 लाख रुपये तथा पुलिसा मरम्मत के 1,161 कार्यों पर 7 करोड़ 20 लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया है। जल संसाधन विभाग के 903 कार्यों के लिए 18 करोड़ 67 लाख रुपये, चिकित्सा विभाग के 700 कार्यों के लिए 13 करोड़ 18 लाख रुपये, पंचायती राज विभाग के 873 कार्यों के लिए 19 करोड़ 39 लाख रुपये, पीएचईडी के 17 कार्यों के लिए 22 लाख 69 हजार रुपये तथा शिक्षा विभाग के 24,531 कार्यों पर 486 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल

विकास विभाग के लिए 7,911 कार्यों के लिए 173 करोड़ 03 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

बारिश और आपदाओं के कारण हुई 112 जनहानि में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 4 करोड़ 48 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के नुकसान, घर के सामान, कपड़ों तथा मकानों की मरम्मत हेतु 11 करोड़ 54 लाख रुपये की सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

राज्य सरकार ने कहा है कि वह प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हर नागरिक के साथ खड़ी है और त्वरित राहत, पारदर्शिता तथा पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

- सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया**
- बारिश और आपदाओं के कारण हुई 112 जनहानि में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई**

सरदार पटेल यूनिटी मार्च में देशभक्ति और एकता का संदेश दिया

जयपुर/सवाई माधोपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में सोमवार को चौथ का बरवाड़ा में भव्य सरदार पटेल यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। गुडला वाले हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ होकर चौथ का बरवाड़ा ट्रस्ट की धर्मशाला तक निकाले गए इस ऐतिहासिक मार्च ने पूरे क्षेत्र में उत्साह,

- भाजपा महामंत्री एवं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने जनसमूह को संबोधित किया**



चौथ का बरवाड़ा में भव्य सरदार पटेल यूनिटी मार्च का आयोजन किया ।

समाजों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं और कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। युवा, बुजुर्ग, महिलाएँ सहित बड़ी संख्या के श्रववासी मार्च में लगातार जुड़ते गए, जिससे इसका स्वरूप और अधिक विशाल व ऐतिहासिक बन गया।

भाजपा महामंत्री एवं खंडार

विधायक जितेंद्र गोठवाल ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और दृढ़ नेतृत्व के प्रतीक हैं। उनकी संतान दुश्मन और राष्ट्रनिर्माण की दूरदर्शिता नवभारत की मजबूत नींव है। उनका जीवन हमें कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की

प्रेरणा देता है। इस यूनिटी मार्च के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने एक स्वर में संदेश दिया एक भारत, श्रेष्ठ भारत, केवल नारा नहीं, हमारा संकल्प है। यूनिटी मार्च में भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, मंडल पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।

विद्युत विभाग का लाईन मैन अपने दलाल साथी सहित रिश्तत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाड़ी टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम मुबारिकपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर के लाइनमैन द्वितीय दिनेश कुमार और प्राइवेट व्यक्ति राजकुमार को पांच हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की भिवाड़ी टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके पिताजी के नाम करीब 3 वर्ष पूर्व फेस कृषि कनेक्शन की पत्रावली सहायक अभियंता जेवीवीएनएल रामगढ़ जिला अलवर में लगाई थी। जिसका डिमांड

- लाइनमैन द्वितीय दिनेश कुमार और प्राइवेट व्यक्ति राजकुमार को पांच हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया**
- शिकायत मिलने पर एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया गया**

नोटिस करीब 10 माह पूर्व उक्त कार्यालय द्वारा जारी किया गया तो उसके द्वारा डिमांड नोटिस राशि जमा करवाई गई।

इस कनेक्शन के पेटे ट्रांसफार्मर की इण्डेन कटवा कर ट्रांसफार्मर देने की एतज में लाइनमैन द्वितीय दिनेश कुमार दिनेश कुमार और दलाल राजकुमार को पांच हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया गया है।

की रिश्तत की मांग की जा रही है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया गया। एसीबी आीम भिवाड़ी के उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वर लाल के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए लाईन मैन द्वितीय दिनेश कुमार और दलाल राजकुमार को पांच हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया गया है।

भगवती पेपर मिल में लगी भीषण आग

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के कालाडरा थाना इलाके में स्थित रीको एरिए में एक पेपर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लाखों रुपए का माल आग की भेंट चढ़ गया। सूचना पर आठ अलग-अलग जगहों की दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के आग आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर रात भगवती पेपर मील में अचानक से आग लग गई थी। जिसमें लाखों रुपए का कच्चा पेपर आग की भेंट चढ़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी अग्निशमन अधिकारी को दी।

मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारी जय कुमार जांगिड़ ने बताया कि मौके पर पहुंचने से आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। जिसे काबू में करने के लिए चोर्म्, जयपुर, कालाडेरा, सरना ड्यूरी, जोलेनर ,रेनवाल, रींगसे और मंडा सहित आठ अलग –अलग जगहों से फायर ब्रेड्रेड की गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टि से आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया।

छात्रों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए आईस्टार्ट कार्यक्रम संचालित

- 7100 से अधिक स्टार्टअप को मिला 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश**

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नवीन उद्यमों को बढ़ावा मिलने से राजस्थान में रोजगार का सृजन और निवेश में वृद्धि हो रही है। शर्मा के निर्देशन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईस्टार्ट कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इसके तहत आईस्टार्ट राजस्थान (एकीकृत स्टार्टअप प्लेटफॉर्म) के माध्यम से प्रदेश में स्टार्टअप को सुविधाएं और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा आईस्टार्ट पोर्टल प्लेटफॉर्म का संचालन और प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे यह देश के बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। इसके साथ 7100 से अधिक स्टार्टअप जुड़े हुए हैं, जिन्हें 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश मिल चुका है, जिससे प्रदेश में 42 हजार 500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। स्टार्टअप को मान्यता, उन्नयन, कोशल विकास, प्रोत्साहन, फंडिंग आईस्टार्ट प्लेटफॉर्म से मिल रही है। स्टार्टअपस से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल बनाया गया है।

आईस्टार्ट पोर्टल सभी प्रोत्साहनों के लिए वन-स्टॉप गेटवे के रूप में कार्य

रनिंग कर्मचारियों के मुद्दों पर निर्णय नहीं लिए जाने पर विरोध-प्रदर्शन किया

जयपुर। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आन्धान पर नार्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन महामंत्री मुकेश माधुर के निर्देश पर नार्थ वेस्टर्न रेलवे एंप्लॉयीज यूनियन के बैनर तले सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे स्थित विभिन्न रनिंग लॉबी पर रेलवे बोर्ड द्वारा रनिंग कर्मचारियों के मुद्दों पर निर्णय नहीं

- जोनल प्रशासन द्वारा मनमर्जी से कार्यवाही करने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया**

लिए जाने एवं जोनल प्रशासन द्वारा मनमर्जी से कार्यवाही करने के विरुद्ध में लोको पायलट एवं गाड़ी प्रबंधक संयुक्त लॉबी जयपुर पर मंडल अध्यक्ष के एस अहलावत, मंडल मंत्री राकेश यादव एजीएस गोपाल मीना की अगुआई में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है।

यूनियन के सहायक मण्डल मंत्री अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि आल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन की कोलकाता में विगत दिनों सम्पन्न कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार यह प्रदर्शन पूरे देश में किया गया। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते के



मंडल अध्यक्ष के एस अहलावत, मंडल मंत्री राकेश यादव एजीएस गोपाल मीना की अगुआई में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया ।

50 हो जाने पर 25 की दर से सभी भत्तों में वृद्धि कर दी गई है, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में अभी तक वृद्धि नहीं हुई है। इसी प्रकार किलोमीटर भत्ते के 70 भाग को आयकर से मुक्त करने का निर्णय अभी तक सरकार ने नहीं लिया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे पर मनमर्जी से कू वार्किंग में बदलाव किया जा रहा है, और रेवाड़ी लॉबी और जयपुर मण्डल

के गाड़ी प्रबंधकों एवम लोको पायलटों सहायक लोको पायलटों समेत रनिंग स्टाफ का तबादला किया जा रहा है जबकि लोको पायलट (मालगाड़ी) के पदों पर प्रधान कार्यालय के निर्देशों के बावजूद पदोन्नित नहीं हो रही है, एकरफर निर्णय करके नई लॉबी खोली जा रही है एवं कैडर रिय्यू इस वर्ष का अभी तक जारी नहीं किया गया है। इन सभी मुद्दों पर लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर,

डिजिटाइजेशन में राजस्थान सभी राज्यों में अग्रणी

जयपुर। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के अंतर्गत गणना प्रपत्र वितरण, सत्यापन तथा डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरे राज्य में सक्रिय रूप से चल रही है। इस अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पिछले 14 दिनों में घर–घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए हैं तथा उन्हें इस बात की विस्तृत जानकारी दी है कि प्रपत्र कैसे भरा जाए और किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की गति लगातार बढ़ रही है और अब तक 1.65 करोड़ गणना प्रपत्र ईसीआईनेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। जिन 12 राज्यों में फेज दू का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है।

छात्रों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए आईस्टार्ट कार्यक्रम संचालित

- 7100 से अधिक स्टार्टअप को मिला 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश**

विशेषज्ञों से संपर्क की सुविधा मिलती है। आईस्टार्ट नेस्ट निवेशकों और सलाहकारों का नेटवर्क है, जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और नवाचारों को विकसित करने में मदद करता है। इस प्रोग्राम के जयपुर में इनक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोहब और भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, पाली और चूरू में आईस्टार्ट नेस्ट इनक्यूबेटर हैं। सभी इनक्यूबेशन सेंटरों में स्टार्टअप के लिए 20०0 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं।

टेक्नो हब देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, इसमें 700 से ज्यादा स्टार्टअप के लिए स्थान है और 1 लाख 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता (महिला स्टार्टअप के लिए 3 लाख रुपये) दी जाती है। इसी प्रकार, सीड चरण में 60 लाख रुपये तक और ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता और इक्विटी के रूप में 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप को आइडिया व प्रोटोटाइप चरण में 2 लाख 40 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता (महिला स्टार्टअप के लिए 3 लाख रुपये) दी जाती है। इसी प्रकार, सीड चरण में 60 लाख रुपये तक और ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता और इक्विटी के रूप में 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

चैटबॉट के माध्यम से बीमार पशुओं के इलाज में अभूतपूर्व पहल

जयपुर। राजस्थान में पशुपालन विभाग ने तकनीकी नवाचार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बीमार पशुओं के उपचार हेतु ‘चैटबॉट प्रणाली’ की शुरुआत की है। इस अनूठी पहल से अब पशुपालक अपने पशुओं की बीमारी, लक्षण और संबंधित समस्याओं की जानकारी सीधे विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें त्वरित चिकित्सा परामर्श प्राप्त हो रहा है। पिछले छः महीने के दौरान प्रदेश में 82713 पशुपालक इस माध्यम से जुड़ कर सलाह ले चुके हैं और 65490 पशुओं को चिकित्सा सहायता दी जा चुकी है।

केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने पशुपालन विभाग राजस्थान के इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों में विस्तारित करने योग्य बताया।

बघेल ने राजस्थान सरकार के इस नवाचार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य राज्यों के लिए भी चैटबॉट मॉडल को अपनाने की बात कही है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चैटबॉट जैसी तकनीकी पहलें पशुपालकों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर पशुपालक को घर बैठे चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो।

विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में चैटबॉट प्रणाली को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने की योजना है, जिससे पशुओं की

बीमारियों का त्वरित विश्लेषण और निदान और भी सटीक हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने भी राजस्थान के 1962 चैटबॉट मॉडल की सराहना करते हुए इस मॉडल को अपने प्रदेश में अपनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कृषि, पशुपालन, डेयरी डवलपमेंट एवं मत्स्य विभाग के उप सचिव एम.बी. माराले ने महाराष्ट्र में संचालित 1962 महापशुधन संजीवनी एप के माध्यम से राजस्थान की तर्ज पर वाइडसर्प चैटबॉट की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा के अनुसार, चैटबॉट प्रणाली ने पशु उपचार सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाया है। इससे न केवल उपचार की प्रक्रिया में तेजी आई है।

6 दिवसीय कार्यशाला संपन्न

जयपुर । राजस्थान पुलिस ने इंडिया पुलिस फाउंडेशन के मार्गदर्शन में एक महत्वाकांक्षी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया ,जिसका उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को पुलिस के महत्व को उत्तरदायित्वों और सामुदायिक सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान शर्मा एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कम्प्युनिटी पुलिसिंग लता मनोज कुमार के निर्देशन व नोडल अधिकारी पंकज चौधरी के नेतृत्व में मुख्य प्रबन्धक आर्षोपाफ पूम अरोड़ा और सेवानिवृत्त आईपीएस विमला मेहरा के सहयोग से यह कार्यक्रम जयपुर शहर और ठाामीण क्षेत्रों के दो चयनित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों लक्ष्मण डूंगरी,लतागोट और एस.के.एन. विद्यालय जोबनर में शुरू हुआ। आईपीएस ने इस पहल के महत्व को रेखांकित किया।कम्प्युनिटी पुलिसिंग को भविष्य की पुलिसिंग के तौर स्थापित करने के साथ उन्होंने बताया।

राजस्थान 2 2 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहा है- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित किया

जयपुर, 17 नवम्बर। सोमवार को फरीदाबाद में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को

- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंजाब के राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली व लद्दाख के उपराज्यपाल तथा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।

कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली देने के संकल्प के तहत, 22 जिलों में दिन में बिजली दे रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी में 2 हजार 215 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

नीतीश ने मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बता दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर “कोई दूसरा विचार” नहीं है। इस बात को साफ कर देने का उद्देश्य यह है कि किसी अंदरूनी खींचतान में या अंतिम समय पर किसी भाजपा नेता का नाम आगे बढ़ाने के दबाव की कोई गुंजाइश न रहे।

और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जेडीयू ने अगली गठबंधन सरकार बनाने के लिए भाजपा के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। इनमें शामिल है:

जेडीयू का स्पीकर पद पर दावा, जिसे विधानसभा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। जेडीयू के लिए एक उपमुख्यमंत्री पद, ताकि सरकार की संरचना में उसकी पकड़ मजबूत रहे।

बिहार के लिए तुरंत विशेष आर्थिक पैकेज, ताकि विकास संबंधी वादे और एनडीए के घोषणापत्र में दिये गए आश्वासन पूरे किए जा सकें।

ये मांगें जेडीयू के अंदर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती हैं, जिससे पाटी है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने पार्टी को बड़ी चुनौती जीत दियाई है, अब पहले की तरह भाजपा के दबाव में काम करने को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, नीतीश का इस्तीफा न देना और भाजपा के साथ उनके बदलते समीकरणों ने संभावित राजनीतिक

बांग्लादेश की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) (आई.सी.टी.) का गठन, बिना किसी वैध अधिकार और अधिकार क्षेत्र के, मनमाते तरीके से किया है। उन्होंने आई.सी.टी. के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और इसे रद्द करने की मांग की है।

हांगी का कहना है कि अधिकारियों ने निष्पक्ष सुनवाई नहीं की और उन्हें अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दिया। जिस तथ्यांकथित अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, उसमें किसी अंतरराष्ट्रीय न्याय संस्था का कोई प्रतिनिधि नहीं था और न ही उसका कोई कानूनी आधार था।

उन्होंने कहा कि यह ट्रिब्यूनल सिर्फ इसलिए बनाया गया है, ताकि अंतरिम सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाया जा सके और छात्र आंदोलन के दौरान और उसके बाद हुए अत्याचारों के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सके। हसीना ने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी छात्र आंदोलनकारियों की हत्या के लिए कोई आदेश नहीं दिया।

आंदोलन, और हसीना के भारत आने के बाद देश में आगजनी, हत्या और अराजकता की लहर फैल गई थीं। अवामी लीग के कई नेताओं और मंत्रियों पर हमले हुए और कुछ की बेरहमी से हत्या की गई। हमारतों को आग लगा दी गई और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। नए फैसले ने देश में अल्पसंख्यकों और अवामी लीग के प्रति निष्ठा रखने वाली राजनीतिक संस्थाओं और राजनैतिक नेताओं पर हिंसा और हमले की आशंका बढ़ा दी है। देश संकट के कगार पर है और हालात बेहद



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की 32वीं बैठक में भाग लिया।

साथ ही, आरडीएसएस के तहत, 33 केवी के 151 सब स्टेशनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में पुलिस मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ाने से औसत प्रतिक्रिया समय 21 मिनट से घटकर अब लगभग 13 मिनट पर आ गया है। इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय घटकर 58 दिन व बलाकार प्रकरणों के निस्तारण का औसत समय घटकर 48 दिन रह गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा के तहत 88 प्रतिशत आबादी का कवरेज हो चुका है, जो देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म दूध पिलाया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान में सहकारिता में अभूतपूर्व काम हुआ है। राज्य ने भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार का आभार

व्यक्त करते हुए कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने से राजस्थान को लाभ मिला है।

इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार स्कसेना, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मान्तरण विरोधी कानून पर राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा

यह नोटिस जयपुर कैथलिक वैंलफेयर सोसायटी की याचिका पर जारी किया गया है

नयी दिल्ली, 17 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान गैरनानूनी धर्मांतरण निषेध कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जयपुर कैथोलिक वेलफैयर सोसाइटी की याचिका पर राज्य और अन्य से जवाब मांगा है। सोसाइटी की याचिका में इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने न्यायालय को अवगत कराया, "हमने विषाधी क्षमता के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में अधिकता का मुद्दा भी उठाया है।"

पीठ ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही शीर्ष न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस पर धवन ने कहा कि वर्तमान याचिका एक बिल्कुल अलग सवाल उठाती है। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे और दूसरे पक्ष को बुलाएंगे, और फिर हम आपकी बात सुनेंगे।"

अदालत ने नोटिस जारी किया और मामले को अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया।

मामले की सुनवाई चार सप्ताह के

- मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती दिए जाने पर 3 नवम्बर को भी राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा था।

बाद होगी।

गत 03 नवंबर को शीर्ष न्यायालय ने इसी कानून के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और राजस्थान सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा था। वर्ष 2025 का

सऊदी अरब में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तेलंगाना सरकार ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्तिके परिजनों को पांच लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि घटना से जुड़े सभी आवश्यक समन्वय और प्रक्रियाओं के लिए

‘स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस गवई ने कहा कि यह उन्हीं (अध्यक्ष) पर निर्भर है कि वे इस मामले का फैसला करना चाहते हैं या अदालत की अवमानना का सामना करना चाहते हैं। यह अदालत की गंभीर अवमानना है। सीजेआई ने यह भी कहा कि अध्यक्ष को 31 अक्टूबर तक निर्णय लेना था। उन्होंने कहा, अगले सप्ताह तक फैसला कर दीजिए या अवमानना का सामना कीजिए। यह उन्हीं को तय करना है। हम पहले ही कह चुके हैं कि दसवीं अनुसूची से जुड़े मामलों में अध्यक्ष को संवैधानिक प्रोटोकेशन प्राप्त नहीं है। उन्हें खुद तय करना होगा कि वह अपना न्यू इयर ईव कहाँ बिताना चाहते हैं। गवई के सामने अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी अध्यक्ष की ओर से पेश हुए। सिंघवी ने आश्वासन दिया कि अध्यक्ष दो सप्ताह के भीतर फैसला कर देंगे।

आतंकवाद को बढ़ावा जारी रखा तो सेना पाकिस्तान को सबक सिखायेगी

नयी दिल्ली, 17 नवम्बर। सेना प्रमुख जनरल उषेन्द्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने केवल ट्रैलर दिखाया था और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखता है तो सेना ने उसे यह सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है कि जिम्मेदार देश को अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा सेना को यह भी पता है कि बैरंग चिट्ठी का जवाब कैसे देना है।

जनरल द्विवेदी ने सोमवार को यहां चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, "मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म शुरू भी नहीं हुई। सिर्फ ट्रैलर दिखाया गया। सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवादी या उनके आका हमारे लिए एक समान हैं। उन्होंने कहा कि सेना अब बैरंग चिट्ठी का जवाब देने के लिए भी तैयार है।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में सकर्तता के लिए लगाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

केन्द्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया- पायलट

उन्होंने टोंक में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया

टोंक, 17 नवम्बर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्वभर में भारत के लोकतंत्र की मिसाल दी जाती थी। पहले के समय में निर्वाचन आयोग पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, सह्रद पर, जहां गांव-ढाणी में यदि एक, दो वोट ही होते थे, तो भी उन तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलकर जाता था, ताकि वहां रहने वाला एक भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रह जाये, इस भावना के साथ चुनाव आयोग काम करता था। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब संस्थाएं मजबूत होती हैं, परन्तु आज केन्द्र की भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं में संघमारी करके लोकतंत्र को कमजोर करने का

- पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सक्रिय रहकर सकर्तता के साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में प्रभावी भूमिका निभायें।

काम किया है।

सचिन पायलट ने आज टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में सकर्तता के लिए लगाये गये कांग्रेस पार्टी के बीएलए के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते

हुए उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कई राज्यों की मतदाता सूचियों की जांच करवाकर उनमें पायी गई त्रुटियों को उजागर किया है। ये त्रुटियां अनजाने में नहीं हुई हैं, ये जान-बूझकर साजिश की गई गलतियां हैं।

पायलट ने कहा कि हमें सक्रिय रहकर सकर्तता के साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना होगा।

कार्यक्रम के बाद पायलट ने टोंक में नवनिर्मित गहलौद पुल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि गहलौद पुल, न्यू हॉस्पिटल सहित टोंक के वृहद प्रोजेक्ट निर्मित होकर तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन से कहा कि सरकार से आग्रह करके तैयार प्रोजेक्ट्स का शीघ्र लोकार्पण कर जनता को सुपुर्द करें।

तेजस्वी को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया

पटना, 17 नवंबर। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने तेजस्वी प्रसाद यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया है।

राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बताया कि पार्टी की आज की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायक दल के नेता का पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें एक सुर से नेता चुन लिया।

यादव ने बताया को आज की बैठक में चुने हुए विधायकों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन को करीब एक करोड़ 85 लाख वोट मिले हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि मतदाताओं ने उसे नकारा नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले सत्ता पक्ष ने अपनी लुभावनी योजनाओं और महिलाओं के खतों में पैसे भेज कर इसकी दिशा मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी पार्टी के 90 प्रतिशत उम्मीदवारों का जीत जाना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर नजर रखेगी और लोगों के बीच जा कर चुनाव आयोग के नकारात्मक कार्यों से जनता को अवगत कराएगी।

ट्रंप का दबाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का बचाव करते हुए कहा कि इस सौदे से पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं पर भारत का तत्परिक निभर्ता कम होने की उम्मीद है, क्योंकि देश, बेहतर कीमतों की तलाश में आयात स्रोतों में विविधता लाने पर विचार कर रहा है।

भारत में घरों में एल.पी.जी. की बिक्री का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी पर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने एल.पी.जी. की पहुँच बढ़ाने के लिए गरीब और ग्रामीण परिवारों को गैस सुविधा देने पर जोर दिया है, ताकि वे परंपरागत और प्रदूषणकारी ईंधनों का उपयोग छोड़ सकें। अमेरिकी एल.पी.जी. के लिए यह ट्रंप अडीए संसय में हुई है, जब भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास में दोनों देशों के बीच ट्रेड सूरसासन कम करना चाहता है। व्यापार तनाव और भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के भारी आयात के बीच, डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने अधिकतर भारतीय सामानों पर कुल 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिए थे। भारत और अमेरिका अब इन टैरिफों को कम करने के प्रयास में बातचीत कर रहे हैं।

भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसकी लगभग 88 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी होती है। हमारा देश तिलचिक्काफाइंड नैचुरल गैस (एल.एन.जी.) के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, हमारी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी मांग आयात से पूरी होती है। पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिका भारत के लिए कच्चे तेल का पाँचवाँ सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है।

बहूत भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता भी है। अगर एल.एन.जी. की बात करें तो भारत की 60 प्रतिशत से अधिक जरूरत आयात से पूरी होती है।

चुनावी हार के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिनिधि की तरह चलाने में उनकी भूमिका पर है।

परिणाम आने के अगले दिन कुछ नेताओं की बैठक हुई, ये वही लोग थे, जो टिकट बाँटने, बड़े फैसले लेने और खुद को पार्टी के मालिक की तरह पेश करने में शामिल रहे। इनमें अजय माकन, वेणुगोपाल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे।

कुल राहुल ने उन 12 राज्यों की बैठक बुलाई है, जहां एसआईआर लागू किया जा रहा है, और वहां के पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं को तलब किया गया है।

बिहार की हार से ध्यान हटाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि सीधे एसआईआर पर चर्चा शुरू

कर दी जाए?

जबकि सबको पता है कि इन राज्यों में कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है और वह कुछ भी करने की हालत में नहीं है।

राज्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चंद्र शर्मा व अन्य ने खंडपीठ के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को खंडपीठ के फैसले पर यथा स्थिति के आदेश देते हुए प्रकरण को तीन माह में तय करने को कहा था। खंडपीठ में इन अभ्यर्थियों की अपील पर 24 नवंबर को सुनवाई होनी है।